Production of Caustic Soda

3142. SHRI MADHAV RAO SCINDIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of industrial licence for caustic soda are not being implemented or are being under utilised;

(b) if so, the extent of licensed production capacity which remains unutilised, indicating the total licensed capacity and actual production during 1979-80 and the half-year ending September, 1980;

(c) the reasons for non-implementation of licences; and

(d) the steps taken and being taken to ensure capacity production of caustic soda?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) (i) All the six industrial licences for Caustic Soda, with a total capacity of 1,41,100 tonnes per annum are at different stages of implementation.

(ii) Due to power shortages, the utilisation of installed capacity was only 72 per cent during the year 1979-80 and 74 per cent during April-September, 1980-81.

(b) There are 33 units engaged in the manufacture of Caustic Soda with an annual installed capacity of 7,65,994 tonnes. The actual production of Caustic Soda during the year 1979-80 was 5,49,662 tonnes and during the half-year April to September 1980, 2,82,841 tonnes.

(c) Does not arise.

(d) Government are taking steps to improve the power availability, which would improve the capacity utilisation. Further, the Government are also encouraging the use of metal anodes instead of graphite anodes which would economise power consumption and thereby increase capacity utilisation.

मध्य प्रदेश में मांड कोयला खानों से कोयले का खनन

3143. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायगढ़ (मध्य प्रदेश) के निकट एक बिजलीघर की स्थापना के प्रस्ताव की अनुमति दिये जाने के बाद, जिसे बाद में मांड कोयला क्षेत्र से जोड़ दिया जाएगा । मांड कोयला क्षेत्र में कोयले के खनन-कार्य को तेज करने हेतु सरकार अथवा कोयला विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा अब तक की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का क्या रवैया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : रायगढ़ के निकट एक बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव अभी तक मंजूर नहीं किया गया है । मांड-रायगढ़ क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रादेशिक सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस क्षेत्र में कोयले के भंडारों की मात्रा का पता लगने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाएगा । इसके बाद कोल इंडिया लि० को अथवा उसकी ऐजेन्सी अर्थात् खनिज गवेषण निगम को विस्तृत समन्वेषण कार्य करना पड़ेगा । यहां पूंजी निवेश का कोई विचार समन्वेषण की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं पूरी हो जाने पर ही किया जा सकता है ।